

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

* Vol-2* *Issue-5* *May 2025*

पर्यावरण जागरूकता: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन**डॉ० मनीषा कुमारी**

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, एस.डी.जी.डी. महाविद्यालय, बेनीपुर, दरभंगा

परिचय

पर्यावरण जागरूकता का अर्थ है अपने पर्यावरण की नाजुकता को समझना और इसके संरक्षण का महत्व समझना। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना पर्यावरण संरक्षक बनने और अपने बच्चों के लिए उज्ज्वल भविष्य बनाने में भागीदारी करने का एक आसान तरीका है। पर्यावरण सभी सजीवों और निर्जीवों के रहने और संचालन का परिवेश है। हम इसमें रहते हैं और अपनी आवश्यकताओं के लिए इसका (दुरुपयोग) करते हैं। अपनी कभी न खत्म होने वाली जरूरतों और मांगों को पूरा करने की प्रक्रिया में हम पर्यावरण पर दबाव डालते रहते हैं। लेकिन जब ये दबाव हमारे पर्यावरण की धारण क्षमता को बढ़ा देते हैं तो यह जीवन को और अधिक प्रभावित करते हुए बड़े बदलाव दिखाते हैं। इसलिए मानव जाति के लिए किसी भी विनाशकारी घटना से बचने के लिए पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। यह मुद्दा भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया में विचाराधीन है और इसलिए हर नागरिक को पर्यावरण क्षरण को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए।

पर्यावरण की स्थिति एक विश्वव्यापी मुद्दा है। वायु और जल प्रदूषण सीमाओं को नहीं पहचानते; एक राष्ट्र में खराब मिट्टी की स्थिति दूसरे देश की खाद्य आपूर्ति को कम कर सकती है। साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों को अलग-अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक प्रमुख अंतर विकसित देशों और विकासशील देशों द्वारा सामना किए जाने वाले पर्यावरणीय खतरों के बीच है। विकसित देशों द्वारा सामना की जाने वाली पर्यावरणीय समस्याएं काफी हद तक उनकी आर्थिक मजबूती और जीवन स्तर के उच्च मानकों का परिणाम हैं। इसके विपरीत, विकासशील देशों द्वारा सामना किए जाने वाले पर्यावरणीय संकट गरीबी का परिणाम हैं। उदाहरण के लिए, तीसरी दुनिया के देशों में अक्सर लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए संसाधनों और स्वच्छता सुविधाओं की कमी होती है।

गरीब किसानों की कटाई-और-जलाओ तकनीक के कारण होने वाली उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई एक और दुविधा है। तीसरी दुनिया के देश अमेरिका और यूरोप की तुलना में बहुत कम उपभोग कर सकते हैं, लेकिन उनकी जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है। इन देशों में प्राकृतिक संसाधनों और सामाजिक सेवाओं का अभाव है, जो आने वाले वर्षों में उनकी बढ़ती आबादी को पर्याप्त भोजन, आश्रय और रोजगार प्रदान करने के लिए आवश्यक होंगे। भारत में पर्यावरण संबंधी कई मुद्दे हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, कचरा प्रदूषण और वन्यजीवन प्राकृतिक आवास प्रदूषण भारत के लिए चुनौती है। 1947 के बीच स्थिति और भी खराब थी। विश्व बैंक के विशेषज्ञों के डेटा संग्रह और पर्यावरण मूल्यांकन अध्ययनों के अनुसार, 1995 से 2010 के बीच, भारत ने अपने पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने और अपने पर्यावरणकी गुणवत्ता में सुधार करने में दुनिया में सबसे तेज़ प्रगति की है। भारत की बढ़ती आबादी भारत के पर्यावरणीय क्षरण का प्राथमिक कारण है। पर्यावरण प्रदूषण देश के लोगों के सामने आने वाली गंभीर समस्याओं में से एक है। देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण और शहरीकरण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं।

प्रस्तुत शोधपत्र जनसंख्या वृद्धि, बढ़ते शहरीकरण और पर्यावरण तथा लोगों के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव की

जांच करने का एक प्रयास हैं। भारत में, मानव संख्या में तेजी से वृद्धि के साथ-साथ भयंकर गरीबी स्थानीय संसाधनों के आधार को समाप्त और प्रदूषित कर रही है, जिस पर वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आजीविका निर्भर करती है। बड़ी संख्या में लोग वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर, स्वच्छ जल और स्वच्छता के बिना रहते हैं। जनसंख्या का पर्यावरण पर प्रभाव मुख्य रूप से पर्यावरण के माध्यम से होता है। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग और अपशिष्टों के उत्पादन के कारण जैव विविधता, वायु और जल प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय तनावों और कृषि योग्य भूमि पर बढ़ते दबाव से भी इसका संबंध है।

भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश

ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला उत्पादक दिल्ली, मुंबई और चेन्नई दुनिया के दस सबसे अधिक आधिक आबादी वाले शहरों में से तीन हैं। भारत दुनिया के सबसे खराब पर्यावरण वाले देशों में से एक है और इसके लिए उसे स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। जल आपूर्ति, स्वच्छता, तूफानी पानी की निकासी, अपशिष्ट जल का उपचार और निपटान, ठोस और खतरनाक कचरे का प्रबंधन, सुरक्षित भोजन, पानी और आवास की आपूर्ति जैसी सेवाओं की कमी शहरी विकास के साथ तालमेल रखने में असमर्थ हैं। इस सभी के कारण प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इसके अलावा अनियोजित तरीके से की गई कार्रवाई भी प्रदूषण के स्तर को बढ़ाती है।

उद्योग का स्थान

शहरी और उप-शहरी क्षेत्रों में यातायात की भीड़, खराब जल निकासी और कचरा जमा होने से गंभीर प्रदूषण की समस्याएँ पैदा होती हैं। हालांकि, ये सभी कारक मिलकर न केवल पर्यावरण की स्थिति को खराब करते हैं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण प्रदूषित क्षेत्रों में रहने वाले लोग प्रदूषण से संबंधित बीमारियों से संक्रमित होते हैं। वायु प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी बीमारियों की घटनाओं में वृद्धि होता है और जल प्रदूषण के कारण गंभीर जल जनित बीमारियों से पीड़ित रागियों की संख्या बढ़ जाती है।

भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। पिछले पचास वर्षों में जनसंख्या में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के कारण तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण की उच्च दर हुई है, जिससे भूमि, वायु और जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। शहरी विकास के कारण प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हुई है और जनसंख्या गंभीर पर्यावरणीय स्वास्थ्य खतरों के संपर्क में आ गई है। शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण अत्यधिक रुग्णता और मृत्यु दर से जुड़ा हुआ है। अत्यधिक भीड़भाड़ और अपर्याप्त आवास प्रदूषण संबंधी बीमारियों जैसे श्वसन संबंधी बीमारियों, तीव्र जल संकट में योगदान करते हैं। जनित रोग, तपेदिक, मेनिनजाइटिस और विभिन्न अन्य बीमारियाँ।

गांवों में लाभकारी रोजगार के अवसरों की कमी और पारिस्थितिकी तनाव जिसके कारण गरीब परिवारों का शहरों की ओर पलायन लगातार बढ़ रहा है। बड़े शहर उभर रहे हैं और शहरी झुग्गी-झोपड़ियाँ फैल रही हैं। शहरों के इस तरह के तेज़ और अनियोजित विस्तार के परिणामस्वरूप शहरी पर्यावरण का क्षरण हुआ है। इसके ऊर्जा, अवास, परिवहन, संचार, शिक्षा, जल आपूर्ति और सीवरेज और मनोरंजक गतिविधियों जैसे बुनियादी सेवाओं की मांगी और आपूर्ति के बीच अंतर को बढ़ा दिया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के लिए मूल्यवान दुर्लभ संसाधन खत्म हो गए हैं। शहरों के संसाधन आधार में कमी आई है। इसका परिणाम वायु और जल की गुणवत्ता में वृद्धि, अपशिष्टों का उत्पादन, मलिन बस्तियों का प्रसार और अवांछनीय भूमि उपयोग परिवर्तन है, जो सभी शहरी गरीबी में योगदान करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की गिरावट और आसुरक्षित जीवन स्थितियों से पर्यावरण और गरीब लोगों के स्वास्थ्य पर असर

पर्यावरण प्रदूषण

पर्यावरण प्रदूषण शब्द का तात्पर्य उन तरीकों से है जिनसे लोग अपने आस-पास के वातावरण को प्रदूषित करते हैं हवा को गैसों और धुएँ से प्रदूषित करते हैं, पानी को रसायनों और अन्य पदार्थों से विषाक्त करते हैं, और बहुत अधिक उर्वरकों और कीटनाशकों से मिट्टी को नुकसान पहुँचाते हैं। इसके अलावा, वे कई अन्य तरीकों से भी अपने आस-पास के वातावरण को प्रदूषित करते हैं। पर्यावरण का क्षरण सामाजिक-आर्थिक, संस्थागत और तकनीकी गतिविधियों के गतिशील परस्पर क्रिया का परिणाम है। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन आर्थिक विकास, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, कृषि की गहनता, ऊर्जा के बढ़ते उपयोग और परिवहन सहित कई कारकों

से प्रेरित हो सकते हैं। गरीबी अभी भी पर्यावरणीय समस्याओं की जड़ में एक समस्या बनी हुई है।

पर्यावरण शिक्षा के लाभ

उत्साह वृद्धि

पर्यावरण शिक्षा व्यावहारिक, संवादात्मक शिक्षा है जो कल्पना को जगाती है और रचनात्मकता को खोलती है। जब पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाता है, तो छात्र अधिक उत्साही होते हैं और सीखने में लगे रहते हैं, जिससे मुख्य शैक्षणिक क्षेत्रों में छात्रों की उपलब्धि बढ़ जाती है।

पर्यावरण शिक्षा न केवल कक्षा के बाहर अनुभवात्मक सीखने के अवसर प्रदान करती है, बल्कि यह छात्रों को वास्तविक दुनिया में संबंध बनाने और अपने सीखे हुए ज्ञान को लागू करने में सक्षम बनाती है। पर्यावरण शिक्षा शिक्षार्थियों को सामाजिक, परिस्थितिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों के परस्पर संबंध को देखने में मदद करती है।

रचनात्मक सोच कौशल

पर्यावरण शिक्षा छात्रों को शोध करने, यह जांचने के लिए प्रोत्साहित करती है कि चीजें कैसे और क्यों होता हैं, और जटिल पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में अपने स्वयं के निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच कौशल को विकसित और बढ़ाकर, पर्यावरण शिक्षा सूचित उपभोक्ताओं, श्रमिकों साथ ही नीति या निर्माताओं की एक नई पीढ़ी को बढ़ावा देने में मदद करती है।

समझ का समर्थन

पर्यावरण शिक्षा छात्रों को मुद्दों के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि पूरी तस्वीर समझी जा सके। यह विभिन्न दृष्टिकोणों और विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता को बढ़ावा देती है।

राष्ट्रीय बहुविषय शिक्षण

पाठ्यक्रम में ई प्रथाओं को शामिल करके, शिक्षक विज्ञान, गणित, भाषा कला, इतिहास और बहुत कुछ को एक समृद्ध पाठ या गतिविधि में एकीकृत कर सकते हैं, और फिर भी सभी विषय क्षेत्रों में कई राज्य और राष्ट्रीय शैक्षणिक मानकों को पूरा कर सकते हैं। कक्षा को बाहर ले जाना या प्रकृति को घर के अंदर लाना अंतः विषय सीखने के लिए एक उत्कृष्ट पृष्ठभूमि या संदर्भ प्रदान करता है।

स्वास्थ्य

पर्यावरण शिक्षा छात्रों को बाहर निकलने और सक्रिय होने में मदद करती है, और कुछ स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मदद करती है जो हम आज बच्चों में देख रहे हैं, जैसे मोटापा, ध्यान की कमी संबंधी विकार और अवसाद। ईई के माध्यम से अक्सर अच्छे पोषण पर जोर दिया जाता है और प्रकृति में बिताए गए अधिक समय के कारण तनाव कम होता है।

समुदाय सशक्त

पर्यावरण शिक्षा समुदाय की भागीदारी के माध्यम से स्थान और कनेक्शन की भावना को बढ़ावा देती है। जब छात्र अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए अधिक जानने या कार्रवाई करने का निर्णय लेते हैं, तो वे समुदाय के विशेषज्ञों, दाताओं, स्वयंसेवकों और स्थानीय सुविधाओं तक पहुंचते हैं ताकि समुदाय को अपने पड़ोस को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय मुद्दों को समझने और उनका समाधान करने में मदद मिल सके।

छात्र और शिक्षक सशक्त

पर्यावरण शिक्षा सक्रिय शिक्षा, नागरिकता और छात्र नेतृत्व को बढ़ावा देती है। यह युवाओं को अपनी आवाज साझा करने और अपने स्कूल और अपने समुदायों में बदलाव लाने का अधिकार देती है। ईई शिक्षकों को अपना स्वयं का पर्यावरण ज्ञान और शिक्षण कौशल बनाने में मदद करता है। मुझे उम्मीद है कि ये "शीर्ष दस" लाभ आपके ईई को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने का आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता देंगे।

भारत में पर्यावरण जागरूकता को 1970 के दशक में संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित पर्यावरण सम्मेलन (1972) के बाद से महत्व मिला। भारत सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल कई गतिविधियों की। 1986 में पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थापना की गई और पर्यावरण संरक्षण पर कानून बनाए गए। यहाँ भारत की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के उद्देश्य को बताना जरूरी है।

1. सुरक्षा, स्वस्थ, उत्पादक और सौंदर्यपरक रूप से संतोषजनक पर्यावरण का संरक्षण और विकास करना;
2. जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ग्रामीण और शहरी बस्तियों का उन्नयन, विकास और प्रबंधन करना;
3. पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और उचित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को शामिल करते हुए ठोस पारिस्थितिक सिद्धांतों पर विकास योजना बनाना।
4. पर्यावरण सुरक्षा प्रौद्योगिकियों, संसाधनों के पुनर्चक्रण और अपशिष्टों के उपयोग को बढ़ावा देना।
5. पहाड़ों, वर्षा वनों, चरागाहों, रेगिस्तानों, आर्द्रभूमि, झीलों, समुद्र तटों, मैंग्रोव, मुहाना लैगून और द्वीप जैसे विशिष्ट आवासों के लिए प्रकृति भंडार और अभयारण्य बनाकर देश में जैविक विविधता का संरक्षण करना;
6. राष्ट्रीय समुद्री अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर पर्यावरण की सुरक्षा करना।
7. पर्यावरण मानदंड विकसित करना तथा निगरानी, सूचना के संग्रह और प्रसार के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करना।
8. विज्ञान परिदृश्यों के साथ-साथ ऐतिहासिक और उनके परिवेश को संरक्षित करें।
9. सभी स्तरों पर पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना और जन जागरूकता पैदा करना।
10. देश के भीतर पारिस्थितिकीविदों, पर्यावरण वैज्ञानिकों, योजनाकारों और उच्चतम गुणवत्ता वाले प्रबंधकों की पर्याप्त जनशक्ति विकसित करना तथा उनके कार्य को राष्ट्रीय विकास के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता देना।

सारांश व निष्कर्ष

देश में जनसंख्या वृद्धि की गति लगातार चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि इसके कई प्रभाव हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है पर्यावरण का क्षरण। अत्यधिक जनसंख्या के परिणाम औद्योगिकीकरण और शहरीकरण हैं। अध्ययन से पता चलता है कि जनसंख्या वृद्धि की गति ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। वनों की कटाई के कारण वन क्षेत्र कम हो गया है, जिसका असर अंततः मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। देश में वायु प्रदूषण की मात्रा भी काफी अधिक है, जिससे सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है और कई बार इससे मृत्यु और गंभीर स्वास्थ्य खतरे भी होते हैं। जल प्रदूषण के मामले में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है, क्योंकि भूजल और सतही जल दोनों के प्रदूषण से विभिन्न जल जनित बीमारियाँ होती हैं। इस शोध पत्र में पर्यावरण के मानव पर चर्चा की गई है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि मानव को पृथ्वी पर जीवित रहना है, तो स्वस्थ जीवन के लिए सभी प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का समय आ गया है। देश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। सूचना, शिक्षा और संचार के माध्यम से आम जनता और स्थानीय नेताओं को बड़ी जनसंख्या के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में शिक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। हरित आवरण को बढ़ाने तथा मौजूदा वनों को संरक्षित करने के लिए स्थानीय स्तर वनरोधण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए।

इसके अलावा पूरे देश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपसर्गों को और तेज किया जाना चाहिए। समय की जरूरत के हिसाब से अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए और उनके उपाये को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नदियों में अपशिष्ट डालने वाले उद्योगों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा, भूजल प्रदूषण को रोकने के लिए लैंडफिल का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। चूँकि झुग्गी-झोपड़ियाँ जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक हैं, इसलिए झुग्गीयों में पानी और स्वच्छता की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक करने के लिए स्कूल स्तर पर अनिवार्य पर्यावरण शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जन और स्थानीय नेताओं को पर्यावरण वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए पर्यावरण की रक्षा करना समय की मांग है।

संदर्भ सूची:-

1. भार्गव, गोपाल, (1992), प्रदूषण और उसका नियंत्रण; मित्तल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
2. श्रीवास्तव, एच0 सी0 और अंजुला सराफ, (2001), "भारत में जनसंख्या और पर्यावरणीय स्वास्थ्य", आर0 एस0 पी0 (पी0जी0) कॉलेज, झरिया द्वारा आयोजित नई सहस्राब्दी में मानव जनसंख्या पर पर्यावरण पर

- पर्यावरणीय गिरावट के प्रभाव पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत पेपर, धपबाद, जनवरी 20–21 2001,
3. दास, आर० सी०, बराल, जे० के०, साहु, एन० सी०, मिसरास, एम० के० (1988): पर्यावरण विभाजन—विकासशील देशों की दुविधा
4. डे, ए० क (2006) पर्यावरण शिक्षा; न्यू ऐज इंटरनेशनल (पी) एलटीडी।

Cite this Article-

'डॉ० मनीषा कुमारी, 'पीर मुहम्मद मूनिस— एक गुमनाम पत्रकार', *Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ)*, ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:05, May 2025.

Journal URL- <https://www.researchvidyapith.com/>

DOI- 10.70650/rvimj.2025v2i5001

Published Date- 03 May 2025